No. I-34020/03/2026-Coord.I
Government of India
Ministry of Home Affairs
***

Major Achievements, significant Development and important events of Ministry of Home Affairs during the month of February, 2026.

1. The following Bills have been assented by the Hon'ble President of India :

    (i) On 19.02.2026, Delhi Court Fee Amendment Bill, 2026.

    (ii) On 23.02.2026, Delhi Shops and Establishments (Amendment) Bill, 2026.

2. The Union Cabinet approved renaming Kerala to 'Keralam' in February 2026.

3. On 08.02.2026, Hon'ble Union Home Minister chaired a security review meeting on Left Wing Extremism (LWE) in Raipur, Chhattisgarh and a review meeting regarding various development works in Chhattisgarh.

4. On 20.02.2026, Hon'ble Union Home Minister, launched Vibrant Villages Programme–II (VVP–II), at a cost of ₹6,839 crore, in Nathanpur village of Assam.

5. On 21.02.2026, Hon'ble Union Home Minister laid the foundation stone of the headquarters of 10th Battalion of the Assam Police in Kamrup, Assam.

6. On 24.02.2026, Hon'ble Union Home Minister chaired a review meeting on assistance to States, for natural calamities.

7. On 26.02.2026, Hon'ble Union Home Minister interacted with personnel of the Sashastra Seema Bal (SSB) in Araria, Bihar, and inaugurated the Border Out Posts at Leti and Inderwa, along with e-inaugurating and laying the e-foundation stones for various SSB projects.

8. In the month of February, the following meetings were convened by Union Home Secretary :

(i) On 03.02.2026, with the Registrar Generals of the High Court of Manipur and Meghalaya

(ii) On 05.02.2026, with the Registrar General of High Court of Gujarat.

(iii) On 23.02.2026, with the e-Committee of the Supreme Court, on the integration of ICJS and CIS.

9. Exhibition on the Naveen Nyaya Sanhita was organised in the UTs of Lakshadweep and DD&DNH to create awareness about the new laws.

10. A demonstration of Nyaya Shruti application was held for e-Committee on 20.02.2026 and for Secretary (Justice) on 26.02.2026.

11. In the Month of February, 2026, following Notifications have been published in the Gazette of India (Extraordinary) :

i) notification No. 4 dated 20.02.2026 regarding promulgation of the "The Lakshadweep Marine Fisheries Regulation, 2026".

ii) Notification No. 5 dated 20.02.2026 regarding promulgation of the "The Lakshadweep (Registration Amendment) Regulation, 2026"

12. A tripartite agreement was signed between Govt. of India, Govt. of Nagaland and representatives of Eastern Nagaland Peoples' Organisation (ENPO), an apex body representing eight recognized Naga tribes of the six eastern districts of Nagaland, on 05.02.2026 in New Delhi. As per agreement, a Frontier Nagaland Territorial Authority (FNTA) shall be created for Eastern Nagaland Region with legislative, executive and financial autonomy within the State of Nagaland to fulfil social, political, economic, educational, cultural and linguistic aspirations of people of the Eastern Nagaland Region.

13. Following meetings of Sub-Committee of National Executive committee (SC-NEC) were held under the Chairmanship of Union Home Secretary:-

(i) Meeting on 11.02.2026 to consider the proposal of central financial assistance for Andhra Pradesh from the Recovery & Reconstruction funding window under National Disaster Response Fund (NDRF);

(ii) Meeting on 13.02.2026 to consider the project proposals (PPRs) of all 10 States viz. Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Maharashtra, Kerala, Meghalaya, Mizoram, Odisha, Uttarakhand and Tamil Nadu.

(iii) Meeting on 19.02.2026 to consider the proposals of Mitigation measures to prevent Erosion in respect of Arunachal Pradesh for financial assistance from the earmarked allocation under NDMF fund.

14. Agreement between the Govt. of the Republic of India and the Govt. of Nepal on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters was signed on 17.02.2026.

15. Vide Gazette Notification / S.O. No. 941(E), dated 20.02.2026, a State-Level Empowered Committee has been constituted under the chairmanship of the Deputy Registrar General, Directorate of Census Operations, West Bengal, for the purpose of processing and disposing of the large number of citizenship applications received under the CAA in the State of West Bengal.

16. On 25.02.2026, a Deportation Manual 2026 was circulated to all State Governments / UT Administration / Border Guarding Forces / Bureau of Immigration / FRROs / FROs, which will be a key document that will serve as an operational guide for various FROs, FRROs, States / UT Administrations, and Border Guarding Forces, for taking appropriate action on prevention, detection, imposing restriction on movement and deportation of illegal migrants.

17. Jogbani Land immigration post has been designated as an authorized IPs for entry of persons holding e-Visa. Vizhinjam, Kollam and Vizhinjam international seaport immigration posts have also been designated as an authorised IPs for entry of persons holding e-visa.

18. 6th India-UK Home Affairs Dialogue (HAD) was held on 27.02.2026. The Government of India Delegation was led by Secretary (BM) and UK delegation was led by Mr. Simon Ridley, Interim Permanent Secretary, Home Office.

19. During the month of February, 2026, “Prakram Padak” was awarded to 04 police personnel’s of states/UTs and CAPF’s/CPOs.

*****

संख्या I-34020/03/2026-समन्वय.I
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
***

फरवरी, 2026 के दौरान गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम और मुख्य कार्यक्रम।

1. भारत की माननीया राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित विधेयकों को स्वीकृति दी गई :

   (i) दिनांक 19.02.2026 को दिल्ली न्यायालय शुल्क संशोधन विधेयक, 2026

   (ii) दिनांक 23.02.2026 को दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026

2. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2026 में केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने को मंज़ूरी दी।

3. दिनांक 08.02.2026 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) पर सुरक्षा समीक्षा बैठक और छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

4. दिनांक 20.02.2026 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने असम के नाथनपुर गांव में 6,839 करोड़ रु. की लागत से वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम- II (वीवीपी-II) का शुभारंभ किया।

5. दिनांक 21.02.2026 को, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने असम के कामरूप में असम पुलिस की 10वीं बटालियन के मुख्यालय की आधारशिला रखी।

6. दिनांक 24.02.2026 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्यों को सहायता पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

7. दिनांक 26.02.2026 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने अररिया, बिहार में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के कर्मियों के साथ बातचीत की तथा लेटी और इंदरवा में सीमा चौकियों का

उद्घाटन किया, साथ ही विभिन्न एसएसबी परियोजनाओं का ई-उद्घाटन और ई-आधारशिला रखी

8. फरवरी माह में, केंद्रीय गृह सचिव द्वारा निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं:

(i) दिनांक 03.02.2026 को, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों के साथ।

(ii) दिनांक 05.02.2026 को, गुजरात उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के साथ।

(iii) दिनांक 23.02.2026 को, ICJS और CIS के एकीकरण के विषय पर, उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ।

9. नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लक्षद्वीप तथा दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में नवीन न्याय संहिता पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

10. दिनांक 20.02.2026 को ई-समिति के लिए और दिनांक 26.02.2026 को सचिव (न्याय) के लिए 'न्याय श्रुति' एप्लिकेशन का प्रदर्शन किया गया।

11. फरवरी, 2026 माह में, भारत के राजपत्र (असाधारण) में निम्नलिखित अधिसूचनाएं प्रकाशित की गई :

i) "लक्षद्वीप समुद्री मत्स्य पालन विनियमन, 2026" के प्रख्यापन के संबंध में दिनांक 20.02.2026 की अधिसूचना सं. 4

ii) "लक्षद्वीप (रजिस्ट्रीकरण संशोधन) विनियमन, 2026" के प्रख्यापन के संबंध में दिनांक 20.02.2026 की अधिसूचना सं. 5

12. भारत सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ), जो नागालैंड के छह पूर्वी जिलों की आठ मान्यता प्राप्त नागा जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष निकाय है, के प्रतिनिधियों के बीच दिनांक 05.02.2026 को नई दिल्ली

में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार, पूर्वी नागालैंड क्षेत्र के लोगों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और भाषाई आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नागालैंड राज्य के भीतर विधायी, कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता के साथ पूर्वी नागालैंड क्षेत्र के लिए एक फ्रंटियर नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण (एफएनटीए) का सृजन किया जाएगा।

13. केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति (एससी-एनईसी) की निम्नलिखित बैठकों का आयोजन किया गया: -

i) दिनांक 11.02.2026 को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के अधीन रिकवरी और पुनर्निर्माण वित्त-पोषण विकल्प से आंध्र प्रदेश के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु ;

ii) दिनांक 13.02.2026 को सभी 10 राज्यों, अर्थात- अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, उत्तराखंड और तमिलनाडु के परियोजना प्रस्तावों (पीपीआर) पर विचार करने हेतु ;

iii) दिनांक 19.02.2026 को एनडीएमएफ निधि के अंतर्गत निर्धारित आबंटन से वित्तीय सहायता के लिए अरुणाचल प्रदेश के संबंध में कटाव को रोकने संबंधी शमनकारी उपायों के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु ।

14. आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता पर भारत सरकार और नेपाल की सरकार के बीच दिनांक 17.02.2026 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

15. दिनांक 20.02.2026 के राजपत्र अधिसूचना/का.आ. सं. 941 (अ) के तहत, पश्चिम बंगाल राज्य में सीएए के अंतर्गत प्राप्त बड़ी संख्या में नागरिकता आवेदनों पर आगे कार्रवाई करने और निपटान के उद्देश्य से उप महापंजीयक, जनगणना कार्य निदेशालय, पश्चिम बंगाल की अध्यक्षता में एक राज्य-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया।

16. दिनांक 25.02.2026 को, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन/सीमा सुरक्षा बलों/आप्रवासन ब्यूरो/एफआरआरओ/एफआरओ को निर्वासन नियमावली 2026 प्रसारित

की गई , जो एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा जो अवैध प्रवासियों की रोकथाम, उनका पता लगाने, आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने और निर्वासन पर उचित कार्रवाई करने के लिए विभिन्न एफआरओ, एफआरआरओ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और सीमा सुरक्षा बलों के लिए एक परिचालन मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा।

17. जोगबनी भूमि आप्रवासन चौकी को ई-वीजा वाले व्यक्तियों के प्रवेश के लिए अधिकृत आईपी के रूप में नामित किया गया। विझिंजम, कोल्लम और विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह आप्रवासन चौकियों को भी ई-वीजा वाले व्यक्तियों के प्रवेश के लिए अधिकृत आईपी के रूप में नामित किया गया ।

18. छठी भारत-यूके गृह मामलों की वार्ता (एचएडी) दिनांक 27.02.2026 को आयोजित की गई जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव (बीएम) ने और यूके के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री साइमन रिडले, होम ऑफिस, अंतरिम स्थायी सचिव ने किया।

19. फरवरी, 2026 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सीएपीएफ/सीपीओ के 04 पुलिस कर्मियों को "पराक्रम पदक" से सम्मानित किया गया।

*****